

उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

S.A.R. Appeal No.- 13/2015-16

- (i) यह अपीलवाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, धालभूम, जमशेदपुर द्वारा आर0पी0 केस नं0-22/2014-15 में दिनांक 19.06.2015 को पारित आदेश के खिलाफ है।
- (ii) अपीलार्थी – गौरी देवी, पति-स्व0 बाबुलाल साह, ग्राम-घाघीडीह, जगदीशपुर रोड, थाना-बागबेड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम।
- (iii) प्रतिवादी – छुट्टु भूमिज, पिता-स्व0 रौड़ेया भूमिज, ग्राम-घाघीडीह, जगदीशपुर रोड, थाना-बागबेड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम।
- (iv) भू-वापसी हेतु भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-
मौजा-घाघीडीह, थाना नं0-1166, खाता नं0-288, प्लॉट नं0-1426 रकवा- 40'x 25' है।

आदेश

1. यह S.A.R. Appeal आवेदन दिनांक 06.07.2015 को भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर द्वारा R.P. Case No.-22/2014-15 में दिनांक 19.06.2015 को पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी Smt. Gouri Devi द्वारा दाखिल किया गया है।

2. निम्न न्यायालय के अभिलेख R.P.Case No.-22/2014-15 में दिनांक 19.06.2015 को पारित प्रश्नगत आदेश में उल्लेखित है, कि “अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा-घाघीडीह, थाना नं0-1166, खाता नं0-288, प्लॉट नं0-1426, रकवा-48'x25' भूमि हाल सर्वे खतियान में रोड़ेया भूमिज, पिता-जगन्नाथ भूमिज के नाम से दर्ज है जो आदिवासी खाते की भूमि है। प्रश्नगत भूमि पर 20 वर्षों से विपक्षी गौरी देवी, पति-स्व0 बाबुलाल साह का दखल है तथा पक्का मकान है। प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण वैधिक नहीं है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-71A के मामला बनता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह रूलींग दी गई है कि जब किसी आदिवासी रैयत की भूमि पर वो काबिज-दाखिल होने का अधिकार हो, पर कोई गैर आदिवासी व्यक्ति काबिज-दाखिल है तो इसे हस्तांतरण माना जायेगा एवं ऐसे मामलों में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-71A प्रभावी होगा। उक्त रूलींग में माननीय उच्चतम न्यायालय का यह Observation है कि धारा-71A में वर्णित प्रावधान एक लाभकारी कानून है जिसको बनाने का उद्देश्य आदिवासी रैयतों की भूमि की रक्षा करना है क्योंकि वो रक्षा करने में असमर्थ है। ऐसे मामलों में न्यायालय को आदिवासी भूमि की रक्षा करने के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 2004(3) JLJR (SC) 103 [2004(3) PLJR (SC)212] में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं 2005(3) JLJR Page No. 477 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा यह रूलींग दी गई है कि यदि अवैध रूप से दखल करने वाले व्यक्ति ने किसी आदिवासी रैयत की भूमि पर उक्त प्रावधान को परास्त करने की नीयत से कोई संरचना खड़ा कर दिया है तो ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति भी देय नहीं होगा। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विभिन्न मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा

